भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-875

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान

875. श्री एम. सेल्वराज:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे हुए सरकारी/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इन संस्थाओं की उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में विशेषकर नए और उभरते क्षेत्रों में ऊर्जा अनुसंधान के विस्तार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसायटी, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2019-22 के दौरान सीपीआरआई को 479.4 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान, सीपीआरआई द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण, ई-कुकिंग, ऊर्जा भंडारण, इत्यादि जैसे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रित क्षेत्रों से संबंधित आरएंडडी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2019-22 के दौरान निम्नलिखित सहित कई प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया हैः

- भारतीय कुकवेयर के लिए उपयुक्त इंडक्शन स्टोव
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के भंडारण के लिए अधिक क्षमता के ग्रेफीन सुपरकैपेसिटर्स
- कम लागत वाले सिलिकॉन रबर इन्सुलेटर
- ताप विद्युत संयंत्र के लिए पुनः संयोजन दहन पश्चात् कार्बन कैप्चर संयंत्र
- ट्रांसफार्मर अनुप्रयोगों के लिए अखाद्य शाक तेल आधारित हरित इन्सुलेटिंग तरल

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान विद्युत ऊर्जा के नवीन एवं उदीयमान क्षेत्रों में अनुसंधान की सहायता हेतु 112 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ एक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) स्कीम स्वीकृत की है।

****